



नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान शनिवार को विधानभवन में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले तथा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के बीच भेंट हुई। इस अवसर पर विधायक श्वेता महाले के साथ रिपब्लिकन पार्टी के पदाधिकारी पुरण मेश्राम, महेंद्र मानकर, बालू घरडे, राजन वाघमारे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मंत्रियों की गैरजिम्मेदारी पर मुंगंटीवार और कांदे का सरकार को 'घर का आहेर'

विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में शनिवार को एक असामान्य दृश्य देखने को मिला, जब सत्तारूढ़ दल के ही वरिष्ठ विधायकों ने सरकार और मंत्रियों की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। विपक्ष की कम संख्या, नेता प्रतिपक्ष के पद का अभाव और आपसी एकजुटता की कमी के कारण महाविकास आघाड़ी का प्रभाव अधिवेशन में कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बढ़ते कथित गैरकारभार पर सरकार का ध्यान खींचना भी मुश्किल हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में सत्ताधारी दल के विधायकों द्वारा ही मंत्रियों की गैरहाजिरी और जवाबदेही पर सवाल उठाए गए।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर मुनंगंटीवार तथा नासिक से शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक सुहास कांदे ने सदन में मंत्रियों

ने बताया कि संबंधित मंत्री उच्च सदन में प्रश्नोत्तर काल के लिए गए हैं और इस विषय पर उन्हें जानकारी दी गई है, इसलिए वे ही उत्तर देंगे। इस पर सुधीर मुनंगंटीवार ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अत्यंत गंभीर अपराध का मामला है और सरकार ने यह कौन-सी नई पद्धति विकसित की है।

राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने लक्षवेधी को अगले दिन के लिए रखने का सुझाव दिया, लेकिन कांदे ने स्पष्ट कहा कि उन्हें संबंधित विभाग और गृह मंत्री का ही उत्तर चाहिए। उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे और मालेगांव प्रकरण में जवाब लेना उनका अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं एक पिता हैं और सदन में मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पिता है, इसलिए इस मामले में जवाब मिलना ही चाहिए।

कुछ देर बाद गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर सदन में उपस्थित हुए। तब सुहास कांदे ने पूरे मामले का विस्तार से विवरण दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी शेखर उर्फ विजय खेरनार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज होने के बाद वही आरोपी पुलिस के साथ खोजबीन में शामिल था। कांदे ने कहा कि उन्होंने स्वयं पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और बच्ची की २३ वर्षीय मां अब तक तीन बार आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है।

कांदे ने भावुक और आक्रामक लहजे में सवाल उठाया कि तीन साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने वाले आरोपी में कानून का कोई डर नहीं रहा क्या। उन्होंने इस मामले में फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई, सक्षम सरकारी वकील की नियुक्ति, महिला न्यायाधीश की नियुक्ति और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा, यहाँ तक कि फांसी देने की मांग की।

इसके अलावा, अवैध उत्खनन और प्रतिबंध के बावजूद हो रही रेत तस्करी के मामले में भी मुनंगंटीवार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मंत्रियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्री बावनकुळे द्वारा दिए गए उत्तर पर असंतोष जताते हुए पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की।

महामार्ग पर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस की फौरी कार्रवाई से जनता को बड़ी राहत

बीड (संवाददाता) - धुले-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर यात्रियों के वाहनों को रोककर, शीशे तोड़कर और हथियार का भय दिखाकर डकैती व जबरन चोरी करने वाले शातिर गिरोह को बीड स्थानीय अपराध शाखा ने फौरी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस सफल पुलिस कार्रवाई में महामार्ग पर हुई एक डकैती और तीन जबरन चोरी सहित कुल चार गंभीर अपराधों का खुलासा हुआ है। लगातार हो रही इन घटनाओं से आम नागरिकों और यात्रियों में भय का वातावरण बन गया था, जिसे दूर करने में पुलिस की यह कार्रवाई अत्यंत सराहनीय मानी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक नवनीत काँवत के आदेश पर महामार्गों पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्थानीय अपराध शाखा का विशेष पथक गठित किया गया था। पुलिस उपनिरीक्षक श्रीराम खटावकर के नेतृत्व में इस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर जांच शुरू की।

जांच के दौरान ११ दिसंबर २०२५ को जानकारी मिली कि आरोपी कळंब (जि. धाराशिव) से केज की ओर आ रहे हैं। सूचना

मिलते ही पुलिस ने फौरी कदम उठाते हुए नाकाबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने वाहन न रोकते हुए भागने का प्रयास



किया, लेकिन पुलिस ने साहस, सतर्कता और कुशल रणनीति का परिचय देते हुए पीछा कर काले रंग की एमजी हेक्टर कार से आरोपियों को धर दबोचा।

उजागर हुए अपराध १. ४ दिसंबर २०२५ - वडगांव डोक (ता. गेवराई): जैकेट पहनकर सड़क पर वाहन रोककर बाहरी राज्य के यात्रियों के साथ मारपीट कर सोना व नकदी लूटी गई। (पो.स्टे. गेवराई, अपराध क्रमांक ७९४/२०२५) २. २५ सितंबर २०२५ -

संभाजी महाराज चौक, बीड: तड़के चालक के सोते समय वाहन का शीशा तोड़कर यात्रियों के साथ मारपीट कर सोना-चांदी



के आभूषण छीने गए। (पो.स्टे. बीड ग्रामीण, अपराध क्रमांक ३१६/२०२५) ३. २० नवंबर २०२५ - होटल दुबई के सामने: खड़े वाहन का शीशा रॉड से तोड़कर हथियार का भय दिखाते हुए कीमती वस्तुएं चुराई गई। (पो.स्टे. बीड ग्रामीण, अपराध क्रमांक ४०२/२०२५) ४. ९ नवंबर २०२५ - धनवडे वस्ती (पाली): रात के समय आईआरबी पार्किंग क्षेत्र में वाहन रोककर जेब से नकदी जबरन निकाली गई।

विशेष बातचीत: प्रोफेसर मिलिंद मराठे - अध्ययन संस्कृति और पुस्तक मेलों पर पुणे में १३/१२/२०२५ से शुरू होने वाले पुस्तक मेले के संदर्भ में नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद मराठे से विशेष बातचीत

साक्षात्कारकर्ता: मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी (अध्यक्ष, रीड एंड लीड फाउंडेशन, छत्रपति संभाजीनगर/औरंगाबाद) मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी: प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद आपके कार्यकाल में महाराष्ट्र में एनबीटी द्वारा दो बड़े और सफल पुस्तक मेले आयोजित किए गए-पुणे में दिसंबर २०२५ में और नागपुर में नवंबर २०२५ में। ये दोनों मेले अत्यंत सफल रहे। सबसे पहले यह बताइए कि इन मेलों के आयोजन के पीछे क्या सोच थी और आप इस सफलता को कैसे देखते हैं? प्रोफेसर मिलिंद मराठे: धन्यवाद, मिर्जा साहब। अध्यक्ष बनने के बाद से हमने महाराष्ट्र में अध्ययन संस्कृति (वाचन संस्कृति) को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है। पुणे और नागपुर-दोनों ही पुस्तक मेले बेहद सफल रहे। पुणे में लाखों लोग आए, और नागपुर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजन हुआ, जहाँ साढ़े पाँच लाख से अधिक आगंतुक पहुंचे। इन मेलों के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं-

किताबों को सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराना, विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों को एक मंच पर लाना, और पढ़ने की आदत को एक उत्सव के रूप में मनाना। हमारा मानना है कि जहाँ ज्ञान की आराधना होती है, वहाँ समाज और देश आगे बढ़ता है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत-यही हमारा संदेश है। मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी: इन पुस्तक मेलों के माध्यम से अध्ययन संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिल रहा है? और पढ़ने का महत्व क्या है? प्रोफेसर मिलिंद मराठे: पुस्तक मेले केवल किताबें बेचने का माध्यम नहीं होते, बल्कि अध्ययन का उत्सव होते हैं। मानव जीवन में विचारों का अत्यंत महत्व है-विचार ही जीवन को बदलते हैं। ये विचार और भावनाएँ पुस्तकों से आती हैं। निरंतर पढ़ने से व्यक्ति नए विचारों से समृद्ध होता है और विभिन्न भावनाओं-खुशी, दुःख, क्रोध आदि-का अनुभव करता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से हजारों जीवन जीता है। जो नहीं पढ़ता, वह केवल अपना ही जीवन जीता है। व्यक्तिव निर्माण के लिए जीवन भर पढ़ना आवश्यक है। ये मेले विशेष रूप से युवाओं और बच्चों को पुस्तकों से



जोड़ते हैं। मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी: वास्तविक अध्ययन क्या है? क्या यह स्कूल की अनिवार्य पढ़ाई से अलग है? प्रोफेसर मिलिंद मराठे: बिल्कुल। अनिवार्य पढ़ाई-जैसे स्कूल की पाठ्यपुस्तकें या नौकरी के लिए पढ़ना-वास्तविक अध्ययन नहीं है। असली अध्ययन वह है जो अपनी इच्छा और आनंद के लिए किया जाए-कविता, उपन्यास, नाटक, बाल साहित्य आदि। हमारा लक्ष्य है कि लोग प्रतिदिन कम से कम १० पृष्ठ अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ें। जब लोग मिलें तो यह पूछें-क्या पढ़ रहे हो?-सिर्फ क्या कर रहे हो? नहीं। मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी:

अध्ययन संस्कृति को बढ़ावा देने में परिवार, स्कूल और समाज की क्या भूमिका है? आपकी रीड एंड लीड फाउंडेशन (औरंगाबाद) के कुछ प्रयास इस दिशा में प्रभावी रहे हैं। क्या आप उनके बारे में बताएँगे? मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी: जी हाँ। हम रीड एंड लीड फाउंडेशन के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे दो प्रमुख प्रयास हैं: १. पैसे बचाओ, किताबें खरीदो (वर्कशॉप चेपशू एशरव डेज़ी): इस पहल के तहत हम लोगों को बचत करने और उसी धन से अच्छी किताबें खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वे पुस्तकों के मालिक बनें और अध्ययन को निवेश के रूप में देखें। २. मरियम मिर्जा मोहल्ला बाल

पुस्तकालय अभियान: इसके अंतर्गत मोहल्लों और छोटी बस्तियों में बच्चों के लिए छोटे पुस्तकालय स्थापित किए जाते हैं, ताकि बच्चों को उनके घर के पास ही आकर्षक बाल साहित्य उपलब्ध हो और वे बचपन से पढ़ने की आदत विकसित करें। प्रोफेसर मिलिंद मराठे: यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, मिर्जा साहब। आपका ज़मीनी स्तर पर किया गया कार्य एनबीटी के उद्देश्यों को सशक्त करता है। अध्ययन संस्कृति को विकसित करना पड़ता है। सेव मनी, रीड बुक्स बचत को पढ़ने से जोड़ता है, और मोहल्ला बाल पुस्तकालय बच्चों तक सुविधा पहुँचाता है-ये दोनों प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। एनबीटी की ओर से हम भी पुस्तकालय नेटवर्क विकसित कर रहे हैं, सामुदायिक पुस्तकालय शुरू कर रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक शांत अध्ययन जैसे बुकिज़ पहल को बढ़ावा दे रहे हैं। मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी: बुकिज़ क्या है और एनबीटी इसे कैसे समर्थन दे रहा है? प्रोफेसर मिलिंद मराठे: शांतनु नायडू की बुकिज़ एक

सामुदायिक रीडिंग पहल है, जहाँ लोग सप्ताहांत में सार्वजनिक स्थानों पर शांति से पुस्तकें पढ़ते हैं और गैजेट्स से दूर रहते हैं। हम इसे पूरे देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही स्कूलों और ग्राम पंचायतों में पुस्तकालयों को सुदृढ़ कर रहे हैं।तकनीक-ऑडियो बुक्स और ई-बुक्स-का उपयोग करके हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच बढ़ाएँगे। हमारा विश्वास है कि इससे चरित्र, बुद्धि और अच्छे संस्कार मजबूत होंगे। मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी: इन प्रयासों से महाराष्ट्र और देश में किस प्रकार का बदलाव अपेक्षित है? प्रोफेसर मिलिंद मराठे: पुणे और नागपुर जैसे मेलों से शानदार शुरुआत हुई है। आगे और शहरों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। हमारी आशा है कि पढ़ना एक सामाजिक गतिविधि बने, एक उत्सव बने। सामूहिक प्रयासों से भारत एक ज्ञानसम्पन्न राष्ट्र बनेगा।मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी: यह बातचीत अत्यंत प्रेरणादायक रही। समय देने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए! प्रोफेसर मिलिंद मराठे: आपका भी धन्यवाद। बढ़ते रहिए, भारत!

पुलिस भर्ती के लिए फरवरी में मैदानी परीक्षा

मई-जून में हो सकती है लिखित परीक्षा

बीड (रिपोर्टर) : वर्तमान में राज्य में १५ हजार ६३१ पदों के लिए पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए राज्यभर से लाखों आवेदन प्राप्त हुए हैं। उम्मीदवारों के आवेदन करने की अंतिम तिथि ७ दिसंबर को समाप्त हो चुकी है और अब आवेदनों की जांच (छाननी) की जा रही है। गृह विभाग की ओर से फरवरी महीने में इन उम्मीदवारों की मैदानी परीक्षा आयोजित करने	की योजना बनाई गई है। पुलिस भर्ती में सशस्त्र पुलिस, कारागृह सिपाही, पुलिस सिपाही, चालक सिपाही और बैंड्समैन जैसे पद शामिल हैं। मैदानी परीक्षा में गोला फेंक, ८०० मीटर और १००० मीटर दौड़ जैसी स्पर्धाएं होती हैं। गोला फेंक प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवारों को तीन अवसर दिए जाते हैं, जिनमें से सबसे दूर फेंके गए गोले के आधार पर अंक दिए जाते हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए	गोले का वजन ७.२६ किलो और महिला उम्मीदवारों के लिए ४ किलो निर्धारित है। मैदानी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम ५० प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद मेरिट के आधार पर प्रत्येक पद के लिए १० उम्मीदवारों का चयन आगे की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। इस बीच, पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे नए पुलिस उम्मीदवारों का	प्रशिक्षण मार्च २०२६ में समाप्त होगा। उससे पहले मैदानी परीक्षा पूरी करने की योजना गृह विभाग ने बनाई है। मैदानी परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके पश्चात अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद अनुमान है कि जुलाई महीने से नए चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण शुरू हो सकेगा। राज्यभर में एक साथ होगी लिखित परीक्षा	मैदानी परीक्षा के बाद सभी पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा राज्यभर में एक साथ आयोजित की जाएगी। मैदानी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए १० उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारों से आवेदन भरते समय एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन करने का आग्रह किया गया था। फिलहाल आवेदनों की जांच प्रक्रिया जारी है।
---	--	---	---	---

अल्पसंख्यक विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग

महा अल्पसंख्यक फोरम ने जिला कलेक्टर से किया अनुरोध

अहमदनगर (आबिद खान):
राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक विकास विभाग के माध्यम से राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। बाटी (इ-छछ) संस्था की स्थापना की गई है और अल्पसंख्यक आयुक्तालय भी गठित किया गया है। इसके बावजूद जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जिला अल्पसंख्यक विकास अधिकारी द्वारा प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर महा अल्पसंख्यक फोरम ने जिला प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है।
इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जाकिर शकलगर, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. असलम बारी, सचिव मोहसिन शेख, वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान पठान, सैयद वहाब, आर्किटेक्ट इश्राद शेख, उर्दू साहित्य परिषद के सचिव आबिद दुल्हे खान, सीनियर सिटिज़न एसोसिएशन के अध्यक्ष खान साहब, सामाजिक कार्यकर्ता अफ़ज़ल भाई शेख, रिहान काज़ी, रिहान गुज़रांवला, बशीर पठान, इस्माइल पापामियान शेख, फ़कीर



मोहम्मद शेख सहित अन्य पदाधिकारियों ने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी एवं जिला योजना अधिकारी दीपक दातिर से मुलाकात कर अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर कार्यालय में अल्पसंख्यक कक्ष की स्थापना, कक्ष के नाम का बोर्ड लगाने, महिला छात्रावास को शीघ्र पूर्ण करने तथा जिला परिषद के उर्दू स्कूलों के शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की।
महा अल्पसंख्यक फोरम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है। सरकारी समितियों ने इस समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य स्तर पर विकास लक्ष्यों और नीतियों की घोषणा की

है, लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण जिला स्तर पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पा रही है।
फोरम ने अपनी मांगों में कहा कि जिला अल्पसंख्यक विकास कार्यालय को प्रभावी रूप से शुरू किया जाए। वर्तमान में जिला योजना अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर यह कार्यालय संचालित किया जा रहा है, जबकि यहां कम से कम एक-दो क्लर्क और एक चपरासी की नियुक्ति आवश्यक है। कार्यालय के बाहर स्पष्ट नामपट्टिका लगाई जाए, आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की जाए और अल्पसंख्यक योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।
इसके अलावा जिला अल्पसंख्यक विकास निगरानी समिति में गैर-सरकारी

सदस्यों की नियुक्ति, समिति की वैसासिक बैठकें आयोजित करने, संयुक्त राष्ट्र के निर्देशानुसार हर वर्ष १८ दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की भी मांग की गई। इसके लिए उपलब्ध अनुदान का उपयोग करने, अल्पसंख्यक आयोग से निधि मांगने और कार्यक्रम की रिपोर्ट आयोग को भेजने की बात कही गई।
बयान में यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यक आयोग द्वारा इस संबंध में एक परिपत्र पहले ही भेजा जा चुका है, इसलिए इन कार्यक्रमों पर अमल किया जाना चाहिए। अन्यथा समाज के प्रति प्रशासनिक गैर-जिम्मेदारी के खिलाफ संबंधित विभाग से शिकायत की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी।
इस पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी दीपक दातिर ने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यक विभाग की विभिन्न सरकारी योजनाओं का अध्ययन किया जा रहा है और उन्हें जिले में प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ संतुलन बनाए रखने का प्रयास-अजित पवार

विशेष प्रतिनिधि
नागपुर -
टीआरटीआई, बाटी, सारथी, महाज्योति और अमृत जैसी स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इन अधिछात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ अधिकाधिक जरूरतमंद और वंचित वर्ग के छात्रों तक पहुँचे, यही महायुति सरकार का उद्देश्य है। इसके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने, उपयुक्त मापदंडों के साथ निर्धारित दिशानिर्देश तय किए जाएँ, यह जानकारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को विधानसभा में दी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के, विशेषकर वे छात्र जिनके लिए विदेश में शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसे अधिकतम छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता देने का सरकार का इरादा है।
बाटी की छात्रवृत्ति से संबंधित प्रश्न पर विधानसभा सदस्य डॉ. नितिन राजत को उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि राज्य सरकार को कुछ स्थानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि टीआरटीआई, बाटी, सारथी, महाज्योति और अमृत जैसी स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का लाभ एक ही परिवार के एक से अधिक छात्रों को मिल रहा है। इस संदर्भ में जानकारी संकलन की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में इन संस्थाओं का आधे से अधिक बजट छात्रवृत्ति पर खर्च हो

रहा है, जिससे अन्य जरूरतमंद छात्रों की योजनाओं के लिए निधि उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
इन स्वायत्त संस्थाओं के वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देने के विषय पर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में अधिछात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को पात्रता मानदंड तय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें छात्रों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर शेष अनुदान वितरण की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। छात्रवृत्ति प्रदान करते समय प्रत्येक घटक के लिए लाभार्थियों की संख्या तय करने संबंधी नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, किस शैक्षणिक स्तर पर कितने छात्रों को लाभ दिया जाएगा, इस पर स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ अधिकाधिक जरूरतमंद और वंचित वर्ग के छात्रों तक पहुँचे, यही महायुति सरकार का मुख्य उद्देश्य है। छात्रवृत्ति मंजूर करते समय संबंधित पाठ्यक्रमों की राज्य एवं समाज के विकास में उपयोगिता, छात्रों की गुणवत्ता तथा उनकी आर्थिक स्थिति का गहन विचार किया जा रहा है, ऐसा भी अजित पवार ने बताया।



मराठी पत्रकार परिषद की राज्यस्तरीय बैठक में बड़ी संख्या में उपस्थित रहें-दिनकर शिंदे

गेवराई (प्रतिनिधि) :
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक, बीड जिले के वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान तथा स्वतंत्रता सेनानी माणिकराव देशमुख के नाम से दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों का वितरण १४ दिसंबर २०२५ को देवडी में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बीड जिले की डिजिटल मीडिया परिषद के सभी पदाधिकारी एवं पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहें, ऐसा आह्वान डिजिटल मीडिया परिषद के बीड जिलाध्यक्ष दिनकर शिंदे ने किया है।
वडवणी तालुका के देवडी स्थित माणिक बाग में आयोजित इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद के मुख्य न्यासी एस. एम. देशमुख, आदर्श गांव योजना के कार्याध्यक्ष पद्मश्री पोपटराव पवार, उपमुख्यमंत्री के स्वास्थ्य कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे, पत्रकार विशाल परदेशी, परिषद के अध्यक्ष मिलिंद आष्टीकर, न्यासी किरण नाईक, शरद पाबळे, कार्याध्यक्ष शिवराज काटकर, महासचिव सुरेश नाईकवाडे, कोषाध्यक्ष मन्सूरभाई, महिला आघाड़ी प्रमुख शोभा जयपूरकर, डिजिटल मीडिया परिषद के प्रदेशाध्यक्ष अनिल वाघमारे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
कार्यक्रम में सुबह ११ से १ बजे तक पुरस्कार वितरण समारोह और दोपहर २ बजे परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर बीड जिले के डिजिटल मीडिया परिषद के सभी तालुकों के पदाधिकारी एवं पत्रकारों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान डिजिटल मीडिया परिषद के बीड जिलाध्यक्ष दिनकर शिंदे ने किया है।



भुखमरी की रोकथाम में विफलता: तीन वर्षों में राज्य में साढ़े चौदह हजार बच्चों की मौत

बच्चों के हिस्से का मक्खन खाने वालों की जांच हो-रोहित पवार

जमीर काजी
नागपुर :
भुखमरी की रोकथाम और कुपोषण उन्मूलन के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद, पिछले तीन वर्षों में राज्य में केवल कुपोषण के कारण साढ़े चौदह हजार बच्चों की मौत होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। क्या सरकार बच्चों के सिर से मक्खन खाने वालों पर कार्रवाई करने का साहस दिखाएंगी? यह सवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने विधानसभा में उठाया।
प्रश्नोत्तर काल के दौरान बोलते हुए रोहित पवार ने कहा कि भुखमरी की रोकथाम और कुपोषण उन्मूलन पर राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन वास्तव में इस धन से पोषण किसका हो रहा है, यह एक गंभीर प्रश्न है। उन्होंने मांग की कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच कर बच्चों के हक पर डाका डालने वालों के असली चेहरे सामने लाए।
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई अधिवेशनों में कुपोषण से होने वाली बाल मृत्यु का मुद्दा उठाया गया, लेकिन सरकार ने केवल छपे हुए उत्तर देने के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब कम से कम सरकार संवेदनशीलता दिखाए और दुनिया देखने से पहले ही दुनिया से विदा हो रहे मासूम बच्चों की

जान बचाने के लिए प्रभावी उपाय करे, ऐसी मांग उन्होंने की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबिटकर द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत लिखित उत्तर में महायुति सरकार के कार्यकाल, यानी वर्ष २०२२-२३ से २०२४-२५ के बीच, राज्य में कुपोषण के कारण १४ हजार ५२६ बाल मृत्यु होने की बात स्वीकार की गई है। ये बाल मृत्यु मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, अमरावती, अकोला

और यवतमाल जिलों में शून्य से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भुखमरी की रोकथाम और कुपोषण से होने वाली बाल मृत्यु को रोकने के लिए राज्य सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। इसके बावजूद कुपोषण की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में विधानसभा में स्नेहा दुबे, मनोज जामसुतकर, चेतन तुपे

सहित अन्य विधायकों ने प्रश्न उठाया था कि क्या कुपोषण के कारण ४९ हजार बच्चों की मौत हुई है। इस पर मंत्री आंबिटकर ने स्पष्ट किया कि कुपोषण से १४ हजार ५२६ बाल मृत्यु हुई हैं।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य २०३० के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर को प्रति एक हजार जीवित जन्म पर १२ से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बीड से होकर गुजरेगा एक और द्रुतगति महामार्ग

मुंबई : संवाददाता
महाराष्ट्र को जल्द ही एक और महत्वपूर्ण द्रुतगति महामार्ग मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने कल्याण-लातूर द्रुतगति महामार्ग को हरी झंडी दे दी है। इस महामार्ग के कारण वर्तमान में १० से ११ घंटे लगने वाली कल्याण-लातूर यात्रा अब मात्र ४ घंटे में पूरी हो सकेगी। विशेष बात यह है कि इस महामार्ग का बड़ा हिस्सा बीड जिले से होकर गुजरेगा, जिससे बीड के विकास को बड़ी गति मिलने की संभावना है।
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल द्वारा प्रस्तावित ४४२ किलोमीटर लंबाई के इस द्रुतगति महामार्ग को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर

में हुई समीक्षा बैठक में मंजूरी दी है। लंबे समय से कागजों तक सीमित यह परियोजना अब वास्तविक क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब संबंधित विभाग द्वारा इस महामार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। इसके पश्चात भूमि अधिग्रहण और नक्शा तैयार करने का कार्य शुरू होगा।
बीड जिले के लिए क्या बदलेगा?
यह महामार्ग अहिल्यानगर, बीड, मांजरसुंबा घाट और अंबाजोगाई होते हुए सीधे लातूर तक जाएगा। इससे बीड जिला सीधे मुंबई-ठाणे-कल्याण औद्योगिक पट्टी से जुड़ जाएगा। इसके

परिणामस्वरूप-
बीड से मुंबई की यात्रा का समय काफी कम होगा।
व्यापारी, उद्योगपति, किसान और विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।
बीड जिले के औद्योगिक, कृषि और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
माळशेज घाट में ८ किलोमीटर लंबी सुरंग इस द्रुतगति महामार्ग के लिए माळशेज घाट में लगभग ८ किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। इससे घाट क्षेत्र का कठिन और समय लेने वाला सफर आसान हो जाएगा। बीड-

अंबाजोगाई-मांजरसुंबा मार्ग अधिक सुरक्षित और तेज बनेगा।
यह महामार्ग आगे लातूर से होते हुए महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा तक जाएगा, जिससे कर्नाटक की ओर जाने वाला यातायात भी सुगम होगा। साथ ही, इस मार्ग को विरार-अलीबाग बहुउद्देशीय मार्गिका से जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य का परिवहन नेटवर्क और मजबूत होगा।
कुल मिलाकर, बीड जिले से होकर गुजरने वाला यह द्रुतगति महामार्ग मराठवाड़ा के लिए विकास का नया एक्सप्रेस साबित होगा और कल्याण-लातूर की दूरी वास्तविक और आर्थिक दोनों अर्थों में और करीब आ जाएगी।